

न्यायालय :- वाचस्पति मिश्र, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय - बैहर

S.T.No./94/2017
Filling No. ST/669/2017
CNR-MP5005-001-020-2017
संस्थित दिनांक-16.01.2017

म0प्र0 शासन द्वारा:- आरक्षी केन्द्र-गढ़ी
जिला-बालाघाट (म0प्र0) - - - - - **अभियोजन ।**

// विरुद्ध //

मोहनदास पिता हरीदास भाषंत उम्र 35 साल जाति पनिका
निवासी-आवासटोला थाना गढ़ी
जिला-बालाघाट (म0प्र0) - - - - - **अभियुक्त ।**

=====

श्री अभिजीत बापट, अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन ।
श्री सुनिल बेले अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त-मोहनदास ।

=====

::: निर्णय :::

(आज दिनांक 28 अप्रैल 2018 को घोषित)

1. आरोपी के विरुद्ध यह आरोप है कि घटना दिनांक 01.04. 2016 से 13.11.2016 के मध्य वार्ड नंबर 2 आवासटोला अंतर्गत थाना गढ़ी जिला बालाघाट में अभियोक्त्री (जिसका नाम रसियो *Bhupendra Sharma v/s Himachal Pradesh, AIR 2003 Supreme Court 4684* तथा *Section 228 A of IPC, 327 (2) (3) of Cr.P.C.*) के परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखा जा रहा है जिसे कि आगे अभियोक्त्री से सम्बोधित किया जाएगा) के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध अथवा सहमति के बिना धारा 375 (क) भा.द.वि. में वर्णित कृत्य कर, इंद्रिय भोग कर बार-बार बलात्कार कर गर्भवती किया ।

2. अभियोजन का मामला यह है कि प्रार्थिया सुषमा राजपूत ने थाना गढ़ी आकर बताया कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री मानसिक रूप से कमजोर थी । मोहल्ले की महिलाओं से पता चला कि

5-6 माह का गर्भ है, पूछताछ करने पर पता चला कि मोहनदास भासंत के द्वारा शादी का झांसा देकर जंगल ले जाकर कई बार बलात्कार किया है जिससे 5-6 माह का गर्भ ठहर गया है, अभियोक्त्री द्वारा यह शिकायत करने पर कि उक्त गर्भ आरोपी से उत्पन्न है तब अभियोक्त्री के अभिभावक एवं सुषमा द्वारा रिपोर्ट लेख कराने के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गढ़ी के अपराध क्रमांक 105/2016 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियोक्त्री को मेडिकल परीक्षण कराया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के अभिभावक को दी गई, अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण कराया गया। अभियोक्त्री को उत्पन्न पुत्र का सेम्पल नमूना लेकर डी.एन.ए. परीक्षण कराया गया, डी.एन.ए. रिपोर्ट प्राप्त की गई, उक्तानुसार सम्यक् विवेचना कर अभियोग पत्र ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, वहां से प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय को उपार्पण कर अंतरण पश्चात् इस न्यायालय में प्रेषित किया गया।

3. चार्ज की स्टेज पर अभियुक्त ने उक्त अपराध से अस्वीकार किया है यह आधार लिया गया है कि रंजिश के कारण साक्षीगण झूठ बोलते हैं। वह घटना के समय रायपुर कमाने गया था उसे झूठा फंसाया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु अवधार्य प्रश्न यह हैं कि:-

1. क्या घटना दिनांक 13.11.16 से 13.11.16 के मध्य अभियुक्त ने अभियोक्त्री की इच्छा के विरुद्ध धारा 375 (क) भा.द. वि. में वर्णित कृत्य बार-बार कर बलात्कार किया जिसके परिणामस्वरूप अभियोक्त्री गर्भवती हुई ?
2. क्या अभियुक्त ने भारतीय दंड अधिनियम की धारा 376 (2) (एन), 376 (2) (के) के अधीन अपराध कारित किया ?

अवधार्य प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का निष्कर्ष :-

5. सर्वप्रथम लैंगिक अपराध के संबंध में अभियोक्त्री की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में विधिक स्थिति की समीक्षा किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत :- **गुरमीत सिंह**

अवलोकनीय है। उक्त न्यायदृष्टांत में निम्न मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। न्यायदृष्टांत :- The State Of Punjab vs Gurmit Singh & Ors on 16 January, 1996 .Equivalent citations: 1996 AIR 1393, 1996 SCC (2) 384 .

The testimony of the victim in such cases is vital and unless there are compelling reasons which necessitate looking for corroboration of her statement, the courts should find no difficulty to act on the testimony of a victim of sexual assault alone to convict an accused where her testimony inspires confidence and is found to be reliable. Seeking corroboration of her statement before relying upon the same, as a rule, in such cases amounts to adding insult to injury. Why should the evidence of a girl or a woman who complains of rape or sexual molestation, be viewed with doubt, disbelief or suspicion? The Court while appreciating the evidence of a prosecutrix may look for some assurance of her statement to satisfy its judicial conscience, since she is a witness who is interested in the outcome of the charge levelled by her, but there is no requirement of law to insist upon corroboration of her statement to base conviction of an accused. The evidence of a victim of sexual assault stands almost at par with the evidence of an injured witness and to an extent is even more reliable. Just as a witness who has sustained some injury in the occurrence, which is not found to be self inflicted, is considered to be a good witness in the sense that he is least likely to shield the real culprit, the evidence of a victim of a sexual offence

is entitled to great weight, absence of corroboration notwithstanding. Corroborative evidence is not an imperative component of judicial credence in every case of rape. Corroboration as a condition for judicial reliance on the testimony of the prosecutrix is not a requirement of law but a guidance of prudence under given circumstances. It must not be over-looked that a woman or a girl subjected to sexual assault is not an accomplice to the crime but is a victim of another persons's lust and it is improper and undesirable to test her evidence with a certain amount of suspicion, treating her as if she were an accomplice. Inferences have to be drawn from a given set of facts and circumstances with realistic diversity and not dead uniformity lest that type of rigidity in the shape of rule of law is introduced through a new form of testimonial tyranny making justice a casualty. Courts cannot cling to a fossil formula and insist upon corroboration even if, taken as a whole, spoken of by the victim of sex crime strikes the judicial mind as probable. In *State of Maharashtra Vs. Chandraprakash Kewalchand Jain* (1990 (1) SCC 550) Ahmadi, J. (as the Lord Chief Justice then was) speaking for the Bench summarised the position in the following words:

"A prosecutrix of a sex offence cannot be put on par with an accomplice. She is in fact a victim of the crime. The Evidence Act nowhere says that her evidence cannot be accepted unless it is corroborated

in material particulars. She is undoubtedly a competent witness under Section 118 and her evidence must receive the same weight as is attached to an injured in cases of physical violence. The same degree of care and caution must attach in the evaluation of her evidence as in the case of an injured complainant or witness and no more. What is necessary is that the court must be alive to and conscious of the fact that it is dealing with the evidence of a person who is interested in the outcome of the charge levelled by her. If the court keeps this in mind and feels satisfied that it can act on the evidence of the prosecutrix, there is no rule of law or practice incorporated in the Evidence Act similar to illustration .

(b) to Section 114 which requires it to look for corroboration. If for some reason the court is hesitant to place implicit reliance on the testimony of the prosecutrix it may look for evidence which may lend assurance to her testimony short of corroboration required in the case of an accomplice. The nature of evidence required to lend assurance to the testimony of the prosecutrix must necessarily depend on the facts and circumstances of each case. But if a prosecutrix is an adult and of full understanding the court is entitled to base a conviction of her evidence unless the same is shown to be infirm and not trustworthy. If the totality of the circumstances appearing on the record of the case disclose that the prosecutrix does not have a strong motive to falsely involve the person charged,

the court should ordinarily have no hesitation in accepting her evidence."

6. उक्त रेसियों के तारतम्य में अभियोक्त्री के बयान की सूक्ष्म समीक्षा की गई। अभियोक्त्री (अ.सा.-5) ने अपने कथन में आरोपी को पहचान किया जाना व्यक्त किया है। आगे यह व्यक्त किया है कि उपस्थित आरोपी ने घटना दिनांक को नर्सरी में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती (Rape) किया था जिससे उसे पुत्र हुआ था जो बाद में खत्म हो गया था। यह भी व्यक्त किया है कि पुलिस ने जिला चिकित्सालय बालाघाट में मेडिकल परीक्षण कराया था तथा सोनोग्राफी की गई थी, सोनोग्राफी रिपोर्ट प्र.पी. 8, सहमति पत्र प्र.पी. 6, घोषणा पत्र प्र.पी. 7, प्र. पी. 8 पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। साक्षी ने प्र.पी. 5 का मौकानक्शा प्र.पी. 5 स्वयं के समक्ष पुलिस द्वारा निर्मित किया जाना व्यक्त किया है।

7. कंडिका क्रमांक 3 में व्यक्त किया है कि जो पुत्र उसे हुआ था जो कि बाद में खत्म हो गया था वह आरोपी के द्वारा छेड़छाड़ (Rape) किए जाने के कारण उत्पन्न होना बताया था। घटना के संबंध में मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन किया जाना व्यक्त किया है।

8. जिरह में स्पष्ट किया है कि न्यायालय में उपस्थित आरोपी के विरुद्ध मोहल्ले वालों एवं पिता के कहने पर रिपोर्ट की थी। आगे व्यक्त किया है कि उक्त संबंध में मीटिंग बैठाई गई थी लेकिन आरोपी ने उसे रखने से मना कर दिया, जुर्म नहीं कुबूला तब विवश होकर रिपोर्ट करना बतलाया है अर्थात् साक्षी के बयान में यह आया है कि उसने अपने अभिभावक एवं मोहल्ले वालों के दबाव में बलात्कार की उक्त रिपोर्ट आरोपी के विरुद्ध संस्थित कराई थी।

9. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अभियोक्त्री (अ.सा.-5) के बयान का यह भाग की घटना दिनांक को आरोपी ने नर्सरी में उसके साथ रेप (Rape) किया विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

10. उक्त संबंध में श्रीमती सुषमा राजपूत (अ.सा.-1) ने व्यक्त किया है कि घटना के संबंध में स्थानीय महिला से जानकारी मिली थी कि अभियोक्त्री गर्भवती है। यह भी व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री मानसिक रूप से कमजोर महिला की श्रेणी में आती है। साक्षी के बयान की कंडिका 1 में यह आया है कि उसने अभियोक्त्री से बातचीत की तो वह रो रही थी लेकिन उसने प्रथम दिन कोई बात नहीं बतायी। बाद में दूसरे दिन अभियोक्त्री से पूछताछ करने पर उक्त गर्भ किससे है तो उसने आरोपी मोहनदास का नाम लिया था तब प्र.पी. 1 की रिपोर्ट लिखाने गई थी जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। लेकिन साक्षी ने जिरह में स्पष्ट किया है कि उसने घटना के पूर्व आरोपी को अभियोक्त्री के साथ कभी नहीं देखा था।

11. साक्षी ने जिरह में यह भी स्पष्ट किया है कि उसके गांव में मोहनदास सरनेम के कई अन्य व्यक्ति भी रहते हैं। जिरह में यह भी स्पष्ट किया है कि मोहल्ले वालों से यह जानकारी प्राप्त हुई नहीं हुई थी कि अभियोक्त्री मोहनदास से गर्भवती है। रिपोर्टकर्ता श्रीमती सुषमा राजपूत ने कंडिका 5 में स्पष्ट किया है कि अभियोक्त्री की मानसिक स्थिति सही नहीं रहती थी तथा वह गलत बात भी बताती है। कंडिका 4 में यह आया है कि उसके थाने पहुंचने के पूर्व पुलिस ने प्र.पी. 1 की रिपोर्ट टाईप कर ली थी जिस पर उसने हस्ताक्षर किए थे। पुनः स्पष्ट किया है कि पुलिस ने उसके बताने पर प्र.पी. 1 की रिपोर्ट लिखी थी अर्थात् श्रीमती सुषमा राजपूत के बयान में यह आया है कि अभियोक्त्री की मानसिक स्थिति अत्यधिक कमजोर है तथा वह गलत बात भी बता देती है। साक्षी ने जिरह में स्वीकार किया है कि आरोपी के नाम के अन्य व्यक्ति उसके मोहल्ले में हैं। चूंकि अभियोक्त्री मानसिक रूप से कमजोर है तथा मानसिक रूप से अस्थिर रहती है। अतः उसके द्वारा गलत व्यक्ति को आलिप्त किए जाने की संभावना मौजूद है।

12. पूर्णिमा थानेश्वर (अ.सा.-2) ने अपने बयान में बताया है कि उसके मोहल्ले में हल्ला होने के कारण घटनास्थल पर गई थी। मोहल्ले वालों ने बताया कि अभियोक्त्री गर्भवती है। आगे व्यक्त किया है

कि उसके द्वारा पूछताछ करने में अभियोक्त्री ने कुछ नहीं बताया। साक्षी को अभियोजन ने प्रतिकूल घोषित कर जिरह किया है। साक्षी ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के तहत परीक्षण किए जाने पर पुलिस कथन प्र.पी. 2 के ई से ई, जी से जी, एफ से एफ सारवान भाग को (Disown) अस्वीकार किया है। जिरह में आया है कि उसने आरोपी को अभियोक्त्री के घर कभी आते जाते नहीं देखा और न ही एक साथ देखा था। श्रीमती हमीदा बी (अ.सा.-3) ने भी समान आशय का अभिकथन किया है।

13. डॉ. डी.के. राऊत (अ.सा.-6) रेडियोलॉजिस्ट का कथन है कि दिनांक 19.11.16 को पुलिस थाना बालाघाट से डॉ. डोंगरे के रेफर करने पर अभियोक्त्री को गर्भ की सोनोग्राफी परीक्षण किए जाने पर बी. पी.डी. 60.6 एम.एस, ए.सी. 180.2 एम.एम., एफ.एल. 45.9 एम.एम थी। प्रोजेक्शन केफेलिक प्लेसेंटा लेफ्ट लेटरल साईड ए.एफ. सामान्य मत सोनोग्राफी परीक्षण के आधार पर गर्भ में जीवित गर्भस्त फिटस जिसकी गर्भ कालीन आयु 24 सप्ताह थी। सोनोग्राफी फिल्म आर्टिकल ए-1 है, रिपोर्ट प्र.पी. 7 है जिसके बी से बी भाग पर हस्ताक्षर है तथा घोषणा प्र. पी. 8 जिसमें गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण नहीं किया गया है, उल्लेख है जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी को जिरह में कोई चुनौती नहीं दी गई है।

14. डॉ. हरीश कुमार मसराम (अ.सा.-7) का कथन है दिनांक 14.11.16 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ रहने के दौरान आरोपी मोहनदास को सक्षमता परीक्षण हेतु लाए जाने पर परीक्षण किया था। आरोपी के प्राइवेट पार्ट पर कोई चोट नहीं थी, आरोपी संभोग करने में सक्षम था। दो सीमन स्लाईड निर्मित कर संबंधित आरक्षक को सौंप दी थी, परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 9-ए है जिस पर ए से ए भाग पर साक्षी के बी से बी भाग पर आरक्षक के हस्ताक्षर है।

15. नीलेश परतेती (अ.सा.-8) निरीक्षक ने विवेचना के दौरान फार्मल विवेचना किया जाना प्रमाणित किया है तथा अभियोक्त्री के बताए अनुसार प्र.पी. 5 का मौकानक्शा निर्मित किया जाना, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किया जाना, अभियोक्त्री एवं अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण कराना तथा आरोपी को गिरफ्तार किया जाना व्यक्त किया है। आगे यह व्यक्त किया है कि दिनांक 23.11.2016 को पुलिस अधीक्षक बालाघाट माध्यम से एफ.एस.एल. ड्राफ्ट भोपाल भेजा था जो प्र.पी. 13 है जिसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है, माल पावती प्र.पी. 14 है। आगे व्यक्त किया है कि दिनांक 17.04.17 को अभियोक्त्री से उत्पन्न मृत पुत्र का डी.एन.ए. प्राप्त कर पुलिस अधीक्षक बालाघाट जाँच हेतु एफ.एस.एल. सागर प्रेषित किया था। एफ.एस.एल. सागर से प्राप्त रिपोर्ट प्र.पी. 17 है। अभियोक्त्री की मानसिक स्थिति की जाँच के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया था, परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 18 है। उक्त साक्षी से समस्त दस्तावेजी कार्यवाही थाने में बैठकर तैयार किए जाने का सुझाव दिए जाने पर साक्षी ने उक्त सुझाव को अस्वीकार किया है। साक्षी ने आक्षेपित विवेचना को फार्मल रूप से किया जाना प्रमाणित किया है।

16. अभिलेख पर प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य देखें तो डी.एन.ए रिपोर्ट प्र.पी. 17 में यह आया है कि मृत बच्चे से प्राप्त बोन प्रदर्श-ए आरोपी मोहनदास प्रदर्श-बी का जैविक संबंध का नहीं है।

:: परीक्षण प्रतिवेदन {न्या.वि.प्र./डीएनए/329/2017} ::

उपरोक्त प्रकरण से संबंधित सीलबंद 03 पैकेट (A,B,C) आरक्षक 529, राजकुमार आरक्षी केन्द्र गढ़ी, जिला बालाघाट के द्वारा दिनांक 18.04.2017 को प्राप्त हुए। उपरोक्त प्रदर्श कागज, कपड़ा के आवरण में तथा EDTA वायल में मेडीकल आफिसर की सील से सीलबंद थे। सील अविकल मिली। उपरोक्त प्रदर्शों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पैकेट अंकित	अंदर पाये गये प्रदर्श/विवरण	किसका/किससे जप्त	यहाँ अंकित
1	A	Bone	Deceased Child	A/Id-6796
2	B	Blood Sample	Accd. Mohandas	A/Id-6797
3	C	Blood Sample	Victim Sanota	A/Id-6798

परीक्षण परिणाम:

उपरोक्त प्रदर्शों से आर्गेनिक एवं ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्शन विधि द्वारा डीएनए प्राप्त किया गया। प्राप्त डीएनए के वांछित जेनेटिक मार्कर का एम्प्लिफिकेशन Multiplex PCR प्रक्रिया द्वारा Power Plex-16 HS किट के साथ किया गया। इस प्रकार प्राप्त एम्प्लिफाईड डीएनए की जेनेटिक एनालाइजर द्वारा जीनोटाइपिंग प्रोफाइल प्राप्त की गई। प्राप्त परिणामों का विश्लेषण Gene Mapper सॉफ्टवेयर ID v3.2 द्वारा किया गया।

Table 1- Power Plex 16-HS किट से प्राप्त परिणाम।

Genetic Markers	Article B A/Id-6797 (Blood of Accd.Mohandas)	Article A A/Id-6796 (Blood of Deceased Child)	Article C A/Id-6798 (Blood of Victim Sanota)
D3S1358	16,16	15,17	17,17
TH01	6,9	6,9	6,6
D21S11	29,29	28,3,31.2	30,31.2
D18S51	13,14	16,16	13,15
Penta E	12,16	13,19	7,16
D5S818	12,13	10,12	10,12
D13S317	11,12	10,10	10,11
D7S820	8,12	10,11	11,11
D16S539	11,12	10,12	10,11
CSFIPO	11,13	11,12	12,12
Penta D	13,13	13,13	10,13
vWA	17,18	14,15	15,17
D8S1179	12,16	13,13	11,13
TPOX	10,12	8,11	8,11
FGA	21,23	21,22	22,24
AMELOGENIN	XY	XY	XX

ऊपर दी गयी तालिका के अनुसार :

- पीडिता/अभियोक्त्री के स्रोत प्रदर्श C, रक्त नमूना (A/Id-6798) से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल में प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर पाये गये

एलील जोड़ों में से एक एलील, मृत बच्चे के स्रोत प्रदर्श A, बोन (A/Id-6796) से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल में प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर पाये गये एलील जोड़ों में उपस्थित है।

- आरोपी मोहनदास के स्रोत प्रदर्श B, रक्त नमूना (A/Id-6797) से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल में जेनेटिक मार्कर पर पाये गये एलील जोड़ों में से एक एलील, मृत बच्चे के स्रोत प्रदर्श A, बोन (A/Id-6796) से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल में जेनेटिक मार्कर पर पाये गये एलील जोड़ों में उपस्थित नहीं है।

अभिमत:— डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग हेतु प्राप्त प्रदर्शों पर किये गये परीक्षण एवं प्राप्त परिणामों के आधार पर निम्नलिखित निशिच्यात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं —

- ◆ मृत बच्चे से प्राप्त बोन (प्रदर्श-A) पीडिता (प्रदर्श-C) के जैविक संबंधी की है।
- ◆ मृत बच्चे से प्राप्त बोन (प्रदर्श-A) आरोपी मोहनदास (प्रदर्श-B) के जैविक संबंधी की नहीं है।

17. अभिलेख पर प्रस्तुत डी.एन.ए. रिपोर्ट से अभियोक्त्री के बयान के इस भाग का मिलान नहीं होता है कि उक्त भ्रूण आरोपी के वीर्य से उद्भूत है अर्थात् डी.एन.ए. रिपोर्ट यह प्रमाणित नहीं करती कि आरोपी द्वारा की गई आक्षेपित Sexual assault से अभियोक्त्री को उक्त भ्रूण उत्पन्न हुआ था।

18. यह भी उल्लेखनीय है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 53(क) एवं 167 (क) में दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा दिनांक 23.06.06 को संशोधन द्वारा स्थापित किए गए हैं। **संतोष कुमार सिंह वि० राज्य (2010) 9 एस.सी.सी. 747** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मत है कि बलात्कार के मामले में डी.एन.ए. परीक्षण प्रतिवेदन महत्वपूर्ण होता है, उस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका प्रतिवेदन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है। उसके आधार पर सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।

I- उक्त निर्णय के पद-65 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मत है कि डी.एन.ए. जैसे आधुनिक वैज्ञानिक तथ्य के बारे में न्यायालय अपनी

राय को भी प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। उक्त मामले में विशेषज्ञ साक्षी डॉ. लालजी सिंह जो कि डी.एन.ए. परीक्षण से 1974 से संबद्ध थे तथा 1987 से ब्रिटेन से भारत वापस आये थे और सी.सी.एम.बी. हैदराबाद में नियुक्त हुये थे। उनके द्वारा डी.एन.ए.फिंगर प्रिंटिंग की कई विधियां विकसित की गई थी जो कि देश में प्रचलित है। उनकी राय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कमलानानथा विरुद्ध तमिलनाडु राज्य (2005) 5 एस.सी.सी. 194 के मामले में मान्य किया था। उक्त मामले में उनके मार्गदर्शन में डॉ. जी.बी. राव द्वारा किये गये परीक्षण को विवादित नहीं किया गया था।

II- वर्तमान मामले में भी डॉ. प्रवीश भाटी वैज्ञानिक अधिकारी जो कि राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर के डी.एन.ए. यूनिट में पदस्थ हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डी.एन.ए. विशेषज्ञ हैं। उक्त प्रयोगशाला डी.एन.ए. परीक्षण हेतु राज्य की एकमात्र प्रयोगशाला है, उसकी विश्वसनीयता को भी बचाव पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है। इसलिये प्रस्तुत रिपोर्ट प्र.पी. 17 अविश्वास का कोई कारण नहीं है। सत्र न्यायाधीश द्वारा प्राप्त संदर्भ विरुद्ध अरविंद 2015(1)एम.पी.एल. जे. (कि.) 167 के मामले में भी डी.एन.ए. रिपोर्ट को अपराध में संलिप्तता प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त माना गया है। इसलिये डॉ० प्रवीश भाटी की रिपोर्ट को भी अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार से विवादित नहीं किया गया है। अतः उनकी रिपोर्ट प्र.पी. 17 पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

III- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भगवानदास विरुद्ध राजस्थान राज्य ए.आई.आर. 1957 सु.को. 589 के मामले में यह व्यक्त किया है कि यह घातक सिद्धांत होगा कि विशेषज्ञ की राय को बिना अन्य समकक्ष विशेषज्ञ की राय के अमान्य कर दिया जाये। संतोष कुमार (उक्त) के मामले में विचारण न्यायालय द्वारा डी.एन.ए. रिपोर्ट को अस्वीकार किये जाने को उचित नहीं माना गया है तथा कांतीदेवी वि. पूसीराम (2001)5 एस.सी.सी. 311 के मामले में दिये गये अभिमतानुसार डी.एन.ए. के संबंध में वैज्ञानिक विशेषज्ञ के द्वारा दी गई राय को निश्चायक माना है।

19. उक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष यह है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः संदेह का लाभ देते हुए आरोपी

मोहनदास भासंत पिता श्री हरिदास भासंत निवासी आवासटोला थाना गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट को धारा 376 (2) (एन), 376 (2) (के) भा.द.वि. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त कर अपास्त किए जाते हैं।

20. मामले में जप्त संपत्ति सीमन स्लाइड, वैजाईनल स्लाइड आदि मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर मुद्रित।

Sd/-

(वाचस्पति मिश्र)

दिनांक :- 28 अप्रैल 2018

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर